



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

सी०ए० नं०-02/1996-97

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा

बनाम्

मे० मेकनली भारत एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

04/01/20

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने नीलाम पत्र पदाधिकारी खनन-सह-उप निदेशक खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका के नीलाम पत्र वाद सं०-2/89-90 आदेश दिनांक-12.12.1995 के विरुद्ध दायर किया है।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा की ओर से सहायक सरकारी वकील का कथन है कि सर्वश्री मेकनली भारत इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड एवं सर्वश्री गैनन उनकर्ली द्वारा सर्वश्री ई०सी०एल०, राजमहल परियोजना, ललमटिया के सी०एच०पी० प्लान्ट इत्यादि के निर्माण में वृहत पैमाने पर लघु खनिज पत्थर बोल्टर, मेटल, चिप्स, मुरम, बालू मिट्टी एवं ईट का व्यवहार किया गया था। इस संबंध में व्यवहृत खनिज के बावत दोनों कम्पनियों को जिला खनन कार्यालय, गोड्डा के पत्रांक-521 दिनांक-19.08.1989 के द्वारा कारण बताओ नोटिश के साथ-साथ आपूरित खनिज का खनिज मूल्य 14,41,800.00 रु० का मांग पत्र निर्गत किया गया था। जबाव अप्राप्त रहने के कारण उक्त राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र मुकदमा सं०-02/89-90 दायर किया गया। दिनांक-12.12.1995 को नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन-सह-उपनिदेशक, खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका द्वारा आदेश पारित किया गया। पारित आदेश में निम्न बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है :-

1. सी०एच०पी० तथा उससे संबंधी सड़क निर्माण में एक लाख घन फुट मुरम/मिट्टी का भी उपयोग किया गया है। मांग पत्र में भी उल्लेख था, परन्तु नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन-सह-उपनिदेशक, खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका के पारित आदेश में उसपर विचार नहीं किया गया। जिससे सरकारी राजस्व की क्षति पहुँची है।

2. नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिनांक-12.12.1995 को पारित आदेश के पृष्ठ सं०-6 में उल्लेखित है कि संवेदक द्वारा अगस्त, 91 तक 23,76,962 घन फुट पत्थर, 5,46,903 घन फुट बालू तथा 20,07,720 अर्द्ध ईट के व्यवहार किया गया है। जिसके विरुद्ध 6,85,793 घन फुट पत्थर तथा 5,88,150 घन फुट बालू का परिवहन चालान दाखिल किया गया था। जिसमें 6,73,793 घन फुट पत्थर तथा 3,76,600 घन फुट बालू का परिवहन चालान सही पाया गया है। तत्पश्चात् अगस्त, 91 तक 3,29,117.90 रुपये का मांग सही दिखाया गया है (आदेश के पृष्ठ संख्या-7 पर दर्शाया गया है)। जबकि उपलब्ध संचिका के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक-799/एम० दिनांक-08.12.1995 जो नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन, संधाल परगना अंचल, दुमका को सम्बोधित है, के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मात्र 2,00,350 घन फुट पत्थर तथा 60,250 घन फुट बालू का परिवहन चालान सही पाया गया है। इस तरह से पत्थर 21,76,612 घन फुट तथा बालू 4,86,653 घन फुट का स्वामित्व का निर्धारण होना चाहिए था। नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा उक्त सत्यापन प्रतिवेदन को दृष्टिगत नहीं किया गया एवं अपने अनुसार स्वामित्व की गणना की गई। फलस्वरूप सरकारी राशि का ह्रास हुआ है जो निम्न गणना के अनुसार दर्शाया जा रहा है :-

खनिज	सही मात्रा एवं उस पर देय स्वामित्व		माननीय न्या० द्वारा दर्शाया गया मात्रा एवं देय स्वामित्व		अन्तर मात्रा एवं देय स्वामित्व	
	घन मात्रा फुट	स्वामित्व	घन मात्रा फुट	स्वामित्व	घन मात्रा फुट	स्वामित्व
पत्थर	21,76,612	3,70,024.00	17,03,369	2,89,571.90	4,73,243	80,452.10
बालू	4,86,653	41,365.51	1,70,303	14,446.00	3,16,350	26,919.51
कुल		4,11,389.51		3,04,017.90		1,07,371.61

3. न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, दुमका माह सितम्बर, 91 से अगस्त, 94 तक 6,00,241 घन फुट पत्थर, 98,063 घन फुट बालू एवं 3,41,324 अर्द्ध ईट के उपयोग का जिक्र है। जबकि देनदार के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद वर्ष 1989-90 में ही दायर की गई थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त व्यवहृत खनिज के स्वामित्व का भुगतान इस नीलाम पत्र मुकदमा से संबंध नहीं रखता है।

4. न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन, संधाल परगना अंचल, दुमका द्वारा पारित आदेश में संवेदक द्वारा व्यवहृत मुरम का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि उक्त निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा एक लाख घन फुट

3
मुख्य का भी उपयोग किया गया है। जिसका निगमानुसार स्वागित्त 0000.00 रु0 देय होता है।

5. न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन, संथाल परगना अंचल, तुमका द्वारा पारित आदेश में सूद भी देय है। गणना करने पर पत्थर, बालू एवं मुख्य पर नियमानुसार देय स्वागित्त 1,15,871.61 रु0 एवं कुल स्वागित्त राशि 4,44,989.51 रु0 पर पारित आदेश की तिथि तक देय सूद 2,66,993.71 रु0 होता है जो कि कुल 3,82,865.32 रु0 देय होता है। जिसकी वसूली प्रमुख नियोजता से किया जाना चाहिए। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता की ओर से अपील की काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नीलाम वाद सं0-2/96-97 दिनांक-25.08.1989 को दायर किया गया है एवं अधियाचना पत्र में खनन पदाधिकारी, देवघर द्वारा मेकनली भारत, ललमटिया एवं गैनन डंकली के नाम से 14,41,800.00 रु0 वसूली हेतु दायर किया है जो तथ्य एवं विधि के आलोक में चलने योग्य नहीं है। अधियाचना पत्र में किसी भी खनिज पदार्थ का विवरण नहीं दिया गया है एवं दोनों कम्पनियों के नाम से उपरोक्त राशि वसूली का वाद दायर किया गया है। दोनों कम्पनी का वाद 12.12.1995 को संतुष्टि के पश्चात समाप्त किया गया है। उपरोक्त वर्णित दोनों वादों का निष्पादन नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा 12.12.1995 को निर्णित किया गया है। दिनांक-12.12.1995 के निर्णय के विरुद्ध अपील 07.11.1996 को 207 दिन के बाद दायर किया गया है। सर्टिफिकेट एक्ट 1914 की धारा 60A के तहत 15 दिन के अंदर दायर करना था, लेकिन 207 दिन के बाद दायर किया गया है, जो कालवाधित है एवं विलम्ब का कोई युक्ति-युक्त एवं संतोष जनक उत्तर दिन प्रतिदिन का नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो जे0सी0आर0 2008 में दर्ज है, उसमें यह निर्धारित किया गया है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 3 के अनुसार न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अगर निर्धारित समय के तहत अगर कोई

वाद अपील एवं कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है तो उसे इस बिन्दु पर खारिज कर दिया जाय। अगर अपील कालवाधित है तो अपील खारिज किया जाय, वर्तमान अपील 2007 दिन वाद दायर किया गया है। मेकनली भारत द्वारा लघु खनिज जो प्राप्त किया एवं चालान आदि का पूर्ण विवरणी के साथ न्यायालय में 19.12.1989 को शपथ पत्र के साथ दायर किया, जिसका विवरण अभिलेख के पृष्ठ 63 पर है देनदार उपयोग किया गया लघु खनिज स्वामित्व एवं शेष का भुगतान 5,01,177 रु० कर दिया गया है। अतः अवैध खनिज का आरोप निराधार है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०-68/1987 सी०डब्लू०जे०सी० नं०-1369/87 पी०एल०जे०आर० 1987, पृष्ठ 920 में वर्णित किया गया है कि संवेदक स्वामित्व एवं शेष भुगतान के लिए दायित्व नहीं है। पी०एल०जे०आर० 1981 पृष्ठ 86, सी०डब्लू०जे०सी० नं०-232/1987 राँची बेंच विल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम् विहार सरकार एवं अन्य वाद में पारित आदेश के आलोक में देनदार नीलागी वाद में निहित राशि का देनदार नहीं है। सभी निर्णयों का छायाप्रति अभिलेख पर संलग्न है। उक्त कार्य पाँच व्यक्तियों को आवंटित किया गया एवं 27.10.95 को शपथ पत्र दायर किया गया जो पृष्ठ 230 से 235 अगस्त 89 तक एवं सितम्बर 1989 से 1991 तथा सितम्बर 91 से अगस्त 1994, पत्थर, बालु इसकी मात्रा को दर्शाया गया है जो दिनांक-26/28.08.1995 द्वारा अदा कर दिया गया है। अधियाचना पदाधिकारी द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक-17.11.94 पृष्ठ 77 पर है एवं 08.12.95 पृष्ठ 260-261 अभिलेख पर उपलब्ध है। अवैध खनिज का कोई नोटिश निर्गत नहीं किया गया है। अगस्त 1991 से तथा सितम्बर 91 से 1994 तक मेकनली भारत द्वारा व्यवहृत एवं वैध परिवहन चालान की मात्रा को घटाने पर 5,11,077.00 रु० शेष एवं स्वामित्व राशि देय है। उक्त राशि के विरुद्ध 4,92,595.60 रु० अदा किया है एवं 18,481.00 रु० 40 पैसा दिनांक-12.12.95 को कोषागार चालान दिनांक-26.12.95 द्वारा अदा किया गया है एवं न्यायालय द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् नीलागी वाद सं०-2/89 समाप्त किया गया एवं पंजी 10 में दर्ज किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला राजमहल परियोजना ईस्टर्न कोल

फिल्ड लिमिटेड, ललमटिया के अन्तर्गत कोल हेन्डलिंग प्लान्ट निर्माण कार्य से संबंधित है। संवेदक सर्वेक्षी मेकनली भारत इंजिनियरिंग एवं उप संवेदक मेमर्स गैगन इंक्ली एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य में खनिज का व्यवहार किया गया था। निर्माण कार्य में व्यवहृत खनिजों का स्वामित्व का विवरण जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :-

खनिज	साही मात्रा एवं उस पर देय स्वामित्व		माननीय न्याय द्वारा दर्शाया गया मात्रा एवं देय स्वामित्व		अन्तर मात्रा एवं देय स्वामित्व	
	घन मात्रा फुट	स्वामित्व	घन मात्रा फुट	स्वामित्व	घन मात्रा फुट	स्वामित्व
पत्थर	21,76,612	3,70,024.00	17,03,369	2,89,571.90	4,73,243	80,452.10
बालू	4,86,653	41,365.51	1,70,303	14,446.00	3,16,350	26,919.51
कुल		4,11,389.51		3,04,017.90		1,07,371.61

अपीलकर्ता का यह भी कथन है कि संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य में एक लाख घन फुट मुरम का भी व्यवहार में लाया गया था। जिसका स्वामित्व 8500.00 रु० देय होता है। उनका यह भी कहना है कि पारित आदेश में निर्माण में व्यवहृत पत्थर, बालू एवं मुरम पर नियमानुसार देय राशि 1,15,871.61 रु० है एवं पारित आदेश में अंकित राशि 4,44,989.51 रु० का सूद 2,66,993.71 रु० होता है। आदेश में सूद की राशि को जोड़ा नहीं गया है। इस प्रकार $1,15,871.61 \text{ रु०} + 2,66,993.71 \text{ रु०} = 3,82,865.32 \text{ रु०}$ देय होता है। लेकिन निम्न न्यायालय के आदेश में अगस्त 91 तक उपयोग में लाये गये खनिज का स्वामित्व देय से संबंधित निम्न विवरण अंकित किया गया है :-

अगस्त, 91 तक	स्वामित्व
पत्थर- 17,03,369 घन फुट	2,89,571.90
बालू- 1,70,303 घन फुट	14,446.00
ईट- 20,07,720 नम्बर	25,100.00
कुल :-	3,29,117.90

जबकि देय राशि का सूद से संबंधित विवरण तथा मुरम का स्वामित्व का उल्लेख में आदेश में नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नीलाम पत्र पदाधिकारी खनन-सह-उप निदेशक खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका के नीलाम पत्र वाद सं०-2/89-90 आदेश दिनांक-12.12.1995 के पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन-सह-अनुमंडल पदाधिकारी,

महामामा को आदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के पारित आदेश में
 देश राशि 3,82,885.32 ₹60 में अभी तक का रूढ़ की राशि का गणना करके
 मुख्य निधोक्ता, राजमहल परियोजना, ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड, ललमटिया
 से चार सप्ताह के अंदर वसूल करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति
 नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महामामा को दें।
 लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
 गोडडा।

उपायुक्त,
 गोडडा।

DB No-22
 12.01.22

Seer
 12.01.22